

BEFORE THE BOARD OF REVENUE MADHYA PRADESH

GWALIOR

III मिश्रानी गंगा भू.सं/2017/6302

Case No. /2017 Revision

Petitioner

श्री 312-110-11
द्वारा आज 26-12-17 को
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 04.01.18 नियत।

26-12-17
कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. Sandeep Kumar, S/o- Shri Ganga Vishan
 2. Anup Kumar, S/o- Shri Ganga Vishan
 3. Ganga Vishan, S/o- Shri Narayan Prashad
- All are R/o- Panwadihaat,
Tehsil- Aron, District Guna

Vs

Respondents

1. State of Madhya Pradesh through Sub Divisional officer ~~Guna~~ District ~~Bhind~~ Aron Dist/ Guna
2. Herprashad, S/o- Shri Bhagwan Singh, Cast Brahmin, R/o- Panwadihaat, Tehsil- Aron, District Guna

26-12-17
शाखा प्रवारी (रा.सं.)
कार्यालय, महाविद्यालय, ग्वालियर

[Handwritten signature]


राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

6

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक

III/निग./गुना/ब.श./2017/6302.
जिला-गुना

स्थान तथा दिनांक	संदीप कार्यवाही तथा आदेश म0प्र0शासन एवं हरप्रसाद	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
12-01-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री आर0एस0 सेंगर अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया ।</p> <p>2- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है । निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 04.12.2017 का अवलोकन कर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित न करते हुए प्रकरण में मात्र धारा 5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण को गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया गया है जहां पर उपभयपक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का समुचित अवसर उपलब्ध है जहां पर वे अपना-अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपित आदेश से वर्तमान में किसी भी पक्ष के हित प्रभावित होने की भी कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>अतः विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं ठोस आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। प्रकरण दा0रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर </p>	